an>

Title: Need to review the decision to privatize various airports in Country - Laid.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): 2009 में पाँच एयरपोर्ट्स- दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलौर एवं नागपुर का निजीकरण किया गया, जिससे हजारों अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि के लोगों को मिल रहा आरक्षण छिन गया । जबकि ये पाँचों एयरपोर्ट्स लाभदायक थे । निजीकरण की नीति बनाते समय कहा गया था कि सिर्फ बीमार एवं घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों एवं विभागों का ही निजीकरण किया जाएगा । अभी हाल में 6 और एयरपोर्ट्स-अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गोवाहाटी, मंगलौर और त्रिवेंद्रम का निजीकरण करने की योजना है, जबकि ये भी लाभकारी एयरपोर्ट्स हैं । अगर इनका निजीकरण किया जाता है, तो 2009 में की गई गलती की ही पुनरावृत्ति होगी ।

नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से माँग करता हूँ कि इन एयरपोर्ट्स का निजीकरण जनहित में तुरंत प्रभाव से रोका जाए ।